



बाज़ार एकाधिकार एवं प्रतस्पर्धा-वरोधी प्रथाएँ

प्रलम्ब के लिये:

बाज़ार एकाधिकार और प्रतस्पर्धा-वरोधी प्रथाएँ, गूगल प्ले स्टोर, भारतीय प्रतस्पर्धा आयोग, प्रतस्पर्धा अधिनियम, 2002

मेन्स के लिये:

बाज़ार एकाधिकार एवं प्रतस्पर्धा-वरोधी प्रथाएँ, भारत में बाज़ार एकाधिकार एवं कानून, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गूगल एवं ऐप डेवलपर्स के बीच एक विवाद सामने आया है, जहाँ गूगल द्वारा लगभग एक दर्जन कंपनियों को एंड्रॉइड ऐप्स के लिये अपने बाज़ार से हटा दिया है।

- इस विवाद में बाज़ार एकाधिकार एवं प्रतस्पर्धा-वरोधी प्रथाओं पर चर्चा शामिल है, जिसमें एंड्रॉइड ऐप बाज़ार पर गूगल का कड़ा नियंत्रण कार्य कर रहा है।

गूगल एवं ऐप डेवलपर्स के बीच मामला क्या है?

- पृष्ठभूमि एवं प्रसंग:
 - गूगल का एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म और इसका ऐप मार्केटप्लेस, गूगल प्ले, भारतीय स्मार्टफोन के पारस्थितिकी तंत्र पर प्रभावी है।
 - ऐप वितरण एवं राजस्व के लिये गूगल प्ले पर उनकी निर्भरता के कारण, भारतीय डेवलपर्स गूगल के नियमों तथा शुल्कों के अधीन हैं।
 - यह विवाद डिजिटल सेवाओं की in-ऐप खरीदारी पर गूगल द्वारा 11% से 30% तक की शुल्क लगाने से उपजा है, जिससे डेवलपर्स नवाचार एवं प्रतस्पर्धा के लिये अत्यधिक होने के साथ ही हानिकारक भी मानते हैं।
- मुद्दे एवं चर्चाएँ:
 - भारत मैट्रिमोनी तथा डिज़िनी + हॉटसटार जैसे प्रमुख अभिकर्ताओं सहित भारतीय ऐप डेवलपर्सों द्वारा आर्थिक बोझ एवं विकल्प की कमी का हवाला देते हुए गूगल द्वारा लागू शुल्क को न्यायालय में चुनौती दी है।
 - भारतीय प्रतस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतस्पर्धा-वरोधी प्रथाओं के लिये गूगल पर जुर्माना लगाया है, जो इसके बाज़ार प्रभुत्व एवं मूल्य निर्धारण नीतियों पर नियामक जाँच का संकेत देता है।
 - यह संघर्ष प्लेटफॉर्म एकाधिकार के साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME), नवाचार एवं उपभोक्ता कल्याण पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक चर्चाओं को रेखांकित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय तुलनाएँ:
 - टेक अभिकर्ताओं तथा ऐप डेवलपर्स के बीच इसी तरह के विवाद विश्व स्तर पर हुए हैं, ऐपल को अपने ऐप स्टोर शुल्क एवं प्रथाओं पर जाँच का सामना करना पड़ रहा है।
 - यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे न्यायक्षेत्रों में कानूनी एवं नियामक कार्रवाईयाँ अवशिवास संबंधी चर्चाओं को दूर करने के साथ डिजिटल बाज़ारों में निष्पक्ष प्रतस्पर्धा को लागू करने के लिये मसाल के रूप में कार्य करती हैं।

प्ले स्टोर कार्य कैसे करता है?

- गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड सैमसंग, वनप्लस, मोटोरोला एवं ओपपो समेत अन्य स्मार्टफोन पर चलता है।
- उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाने वाले फोन में कुछ गूगल ऐप्स और प्ले स्टोर पहले से इंस्टॉल आते हैं।
- लेकिन नया ऐप जोड़ने के लिये यूज़र को प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड करना होगा।
- गूगल पर ऐप्स के पास डिजिटल सेवाओं के लिये भुगतान स्वीकार करने के तीन विकल्प हैं, गूगल की बलिंग प्रणाली, वैकल्पिक भुगतान जहाँ कंपनी

कमीशन प्राप्त करती है और उपभोग मोड जहाँ डेवलपर भुगतान स्वीकार करने के लिये उपयोगकर्ता को बाह्य वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करता है।

बाज़ार एकाधिकार क्या है?

■ परिचय:

- बाज़ार एकाधिकार उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक एकल कंपनी या कंपनियों का समूह किसी विशेष बाज़ार या उद्योग के महत्त्वपूर्ण हिस्से पर हावी होता है और नियंत्रित करता है।
- एकाधिकार में, केवल एक विक्रेता या निर्माता होता है जो एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा प्रदान करता है और उपभोक्तकों के लिये कोई करीबी विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
- यह एकाधिकारवादी इकाई को पर्याप्त बाज़ार शक्ति प्रदान करता है, जिससे उसे बाज़ार की स्थितियों को प्रभावित करने, कीमतें निर्धारित करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।

■ बाज़ार एकाधिकार की विशेषताएँ:

○ एकल विक्रेता या निर्माता:

- एकाधिकार में, केवल एक इकाई होती है जो पूरे बाज़ार पर हावी होती है। यह कंपनी किसी विशेष उत्पाद या सेवा की अनन्य प्रदाता है।

○ प्रवेश में उच्च बाधाएँ:

- एकाधिकार अक्सर तब उत्पन्न होता है जब नए प्रतस्पर्धियों को बाज़ार में प्रवेश करने से रोकने वाली महत्त्वपूर्ण बाधाएँ होती हैं। बाधाओं में उच्च स्टार्टअप लागत, संसाधनों तक विशेष पहुँच, सरकारी नियम या मज़बूत ब्रांड वफादारी शामिल हो सकती हैं।

○ कोई विकल्प न होना:

- एकाधिकारवादी कंपनी द्वारा पेश किये गए उत्पाद या सेवा के लिये उपभोक्तकों के पास सीमिति या कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है। बाज़ार में इसका कोई करीबी विकल्प उपलब्ध नहीं है।

○ बाज़ार की शक्ति एवं मूल्य नियंत्रण:

- एकाधिकार बाज़ार में अत्यधिक शक्ति होती है, जो उसे प्रतस्पर्द्धा के महत्त्वपूर्ण डर के बिना कीमतों को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान करता है। इससे उपभोक्तकों के लिये कीमतें अधिक हो सकती हैं और संभावित रूप से उत्पादन में कमी आ सकती है।

○ आपूर्ति पर प्रभाव:

- एकाधिकार का उत्पाद या सेवा की आपूर्ति पर नियंत्रण होता है। यह उत्पादित मात्रा निर्धारित कर सकता है और साथ ही बाज़ार को प्रभावित करने के लिये आपूर्ति को समायोजित कर सकता है।

○ प्रतस्पर्द्धा का अभाव:

- प्रतस्पर्द्धियों की अनुपस्थिति के कारण, एकाधिकार ऐसे वातावरण में संचालित होते हैं जहाँ उनके विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिये कोई सीधी प्रतस्पर्द्धा नहीं होती है। प्रतस्पर्द्धा की इस कमी के परिणामस्वरूप नवाचार एवं दक्षता के लिये प्रोत्साहन में कमी आ सकती है।

प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं से संबंधित प्रमुख शर्तें क्या हैं?

■ बेहद सस्ती कीमत:

- बेहद सस्ती मूल्य निर्धारण तब होता है जब कोई कंपनी प्रतस्पर्द्धियों को बाज़ार से बाहर करने के लिये जानबूझकर अपनी कीमतें लागत से कम निर्धारित करती है। एक बार जब प्रतस्पर्द्धा समाप्त हो जाते हैं, तो कंपनी घाटे की भरपाई करने एवं एकाधिकार स्थिति का लाभ प्राप्त करने के लिये कीमतें बढ़ा सकती है।

■ कार्टेल:

- कार्टेल स्वतंत्र कंपनियों या राष्ट्रों के समूह हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण, बिक्री तथा वितरण को नियंत्रित करने के लिये एक साथ आते हैं।
- कार्टेल आमतौर पर अवैध होते हैं और प्रतस्पर्द्धा वरीधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये जाने जाते हैं।

■ वलिय:

- वलिय में दो या दो से अधिक कंपनियों का एक इकाई में संयोजन शामिल होता है। हालाँकि सभी वलिय प्रतस्पर्द्धा-वरीधी नहीं हैं, कुछ वलिय किसी विशेष बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा को कम कर देते हैं, जिससे नियामक जाँच हो सकती है।

■ मूल्य निर्णय:

- मूल्य भेदभाव तब होता है जब एक विक्रेता एक ही उत्पाद या सेवा के लिये अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग कीमतें वसूलता है। हालाँकि यह हमेशा अवैध नहीं होता है, लेकिन अगर यह प्रतस्पर्द्धा को नुकसान पहुँचाता है तो इसे प्रतस्पर्द्धा-वरीधी माना जा सकता है।

■ मूल्य निर्धारण समझौते:

- मूल्य निर्धारण में प्रतस्पर्द्धियों के बीच उनके उत्पादों या सेवाओं के लिये एक विशिष्ट मूल्य निर्धारित करने हेतु एक समझौता शामिल होता है। यह प्रतस्पर्द्धा को समाप्त करता है और बनावटी रूप से कीमतें बढ़ाता है, जिससे अवशिष्ट कानूनों का उल्लंघन होता है।

बाज़ार के एकाधिकार से नपिटने के लिये भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पहल क्या हैं?

■ भारतीय:

- **प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:** [प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002](#) भारत में अवशिवास मुद्दों को हल करने वाला प्राथमिक कानून है। इसे बाज़ारों में प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं को रोकने एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये अधिनियमि कथिया गया था।
 - **प्रतस्पर्द्धा संशोधन अधियक, 2022:** प्रस्तावति संशोधन का उद्देश्य नयामक फरेमवरक को और सुदृढ़ करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना तथा प्रतस्पर्द्धा कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।
- **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):** [CCI](#) भारतीय बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रतस्पर्द्धा का नयामक है। यह प्रतस्पर्द्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिये ज़मिमेदार है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नयिकृत एक अधयकष व अन्य सदस्य होते हैं।
 - CCI प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं, प्रमुख स्थतिके दुरुपयोग और प्रतस्पर्द्धा-वरीधी समझौतों की जाँच करती है एवं कार्रवाई करती है।
- **प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण और NCLAT:** [प्रतस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण](#) शुरु में CCI के नरिणयों के खलिफ अपील सुनने के लिये ज़मिमेदार है।
 - हालौकविर्ष 2017 में, सरकार ने COMPAT को [राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण](#) से प्रतस्पर्द्धापति कर दिया, जो अब प्रतस्पर्द्धा मामलों से संबधति अपीलों को संभालता है।

■ अंतरराष्ट्रीय पहल:

- **OECD प्रतस्पर्द्धा समति:** [आर्थिक सहयोग और वकिस संगठन OECD प्रतस्पर्द्धा समति](#) सहति वभिन्नि पहलों के माध्यम से प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं से नपिटता है, जो प्रतस्पर्द्धा से संबधति मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा और सहयोग की सुवधि प्रदान करता है।
- **व्यापार और वकिस पर संयुक्त राष्ट्र सममेलन:** यह प्रतस्पर्द्धा कानून और नीतिपर अपने अंतर सरकारी वशिषज्जों के समूह के माध्यम से प्रतस्पर्द्धा नीति व कानून पर मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा प्रभावी प्रतस्पर्द्धा फरेमवरक को लागू करने में राष्ट्रों का समर्थन करता है।
 - यह **उपभोक्ताओं का दुरुपयोग से संरक्षण** और प्रतस्पर्द्धा को बाधति करने वाले नयिमों पर अंकुश लगाने की नीतियों के वषिय में भी कार्य करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतस्पर्द्धा नेटवरक (ICN):** ICN समगर वशिव के **प्रतस्पर्द्धा प्राधिकरणों का एक नेटवरक** है। यह वैश्विक प्रतस्पर्द्धा चुनौतियों से नपिटने के लिये सदस्य न्यायालयों के बीच संचार और सहयोग की सुवधि प्रदान करता है।
 - ICN, प्रतस्पर्द्धा कानून के वभिन्नि पहलुओं पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और दशिन-नरिदेश तैयार करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- **वशिव व्यापार संगठन (WTO):** मुख्य रूप से व्यापार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करते हुए, [WTO](#) व्यापार और प्रतस्पर्द्धा नीतिके बीच वारता पर कार्य समूह के माध्यम से **प्रतस्पर्द्धा नीतिके संबोधति करता है**।
 - इसका उद्देश्य प्रतस्पर्द्धा नीतियों के कारण व्यापार में अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न होने से बचाना है।

आगे की राह

- सार्वजनिक नीति वशिषज्ज और उद्योग प्रतनिधि जैसे समर्थक **प्रतस्पर्द्धा** बढ़ाने तथा ऐप स्टोर गेटकीपरों के **प्रभुत्व को कम करने** के लिये नयामक सुधारों का प्रस्ताव कर सकते हैं।
- ऐप स्टोर नीतियों में पारदर्शति और नषिकषता को अनविरय बनाना, अधिक भुगतान वकिल्पों के साथ डेवलपरस को सशक्त बनाना तथा वैकल्पिक वतिरण चैनलों के उदभव को सुवधाजनक बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- **प्लेटफॉर्म प्रदाताओं, डेवलपरस और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलति करने के लिये नवाचार, प्रतस्पर्द्धा तथा उपभोक्ता कल्याण को प्राथमकता देने वाले एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय वधिान के प्रावधानों के अंतरगत उपभोक्ताओं के अधिकारों/वशिषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खादय की जाँच करने के लिये नमूने लेने का अधिकार है।
2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में शकियात दर्ज करता है तो उसे इसके लिये कोई फीस नहीं देनी होती।
3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शकियात दर्ज कर सकता है।

नमिन्लखिति कूटों के आधर पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. क्या वर्ष 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, नजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के लिये भारत सरकार की व्यवस्था ने पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दी है? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रतित्तरदायी होने के लिये सरकार क्या कर सकती है? (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/market-monopoly-and-anti-competitive-practices>

